communications, helping the residents of nearby rid adjacent villages; and

(d) if so, the details of the action proposed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir. Two post offices in the hill region of Uttar Pradesh, viz., Nainital H.O. and Tallital SO are covered by the programme of modernisation during the year 1995-96.

(b) Yes, Sir. There are instances of delay to mail in the hill regions and remote interior areas of Uttar Pradesh characterised by difficult terrain and weather, and irregular plying of mailcarrying buses. Seasonally, problem of transport becomes more difficult, causing delay. Mail also suffers delay in some of these regions due to public agitations now and then. Department of post monitors closely the transmission and delivery of mail in such areas and wherever failures are notices, corrective steps are promptly taken.

(c) There is no proposal to upgrade the post office at village Bedgaon in Patti Maniyarsuen(Poorvi) Pauri Garhwal.

(d) Does not arise in view of (c) above.

यमुना नदी के दूषित जल के शोधन हेतु धनराशि का आवंटन

562. **श्री रामजीलाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार यमुना नदी के दूषित जल के शोधन हेतु कोई धनराशि प्रदान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षो के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई हैं तथा 1994-95 और 1995-96 के वर्षो के दौरान हरियाणा को विशेष रूप से कितनी धनराशि प्रदान की गई हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इसके जल को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से दूषित जल के शोधन हेतु हरियाणा को अधिकतम कितनी सहायता राशि प्रदान कर सकती हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, यमुना नदी के प्रदूषण निवारण के लिए सरकार ने यमुना कार्य योजना नामक स्कीम का अनुमोदन किया हैं। इस स्कीम की पूंजीगत लागत केन्द्र सरकार और हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की राज्य सरकार के बीच बराबर की हिस्सेदार होगी। स्कीम में केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में तीनों राज्यों का अनुदान के रूप में अब तक 28.30 करोड़ रूपये की राशि दी जा चुकी हैं। दी गई राशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं (**नीच देखिए**)। इस स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा सरकार को वर्ष 1994-95 में 1.50 करोड़ रूपये और वर्ष 1995-96 के दौरान 3.00 करोड़ रूपये की राशि दी गई।

(ग) यमुना कार्य योजना में हरियाणा में कार्यो की वर्तमान स्वीकृत लागत 113.85 करोड़ रूपये हैं। इस प्रकार केन्द्र से हरियाणा को प्राप्त अनुदान की राशि 56.93 करोड़ रूपये तक सीमित होगी जो कि संस्वीकृत लागत का 50% हैं।

विवरण

यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा

(**करोड़ रूपये**)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96	**योग**
हरियाणा	6.96	1.50	3.00	11.46
उत्तर प्रदेश	8.74	2.35	3.68	14.77
दिल्ली	0.24	-	1.83	2.07
योग	15.94	3.85	8.51	28.30

Telecom Regulatory Authority

563. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a three-Member Telecom Regulatory Authority was constituted recently;
and

(b) if so, what are its functions and by when
it will start functioning?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) The Telecom Regulatory Authority of India Bill, 1996 has been introduced in the Lok Sabha on 27.2.1996 for replacing the Ordinance promulgated by the President on 27.1.96 for constituting the Telecom regulatory Authority of India.

The authority shall consist of a Chairperson, and not less than two, but not exceeding four members, to be appointed by the Central Government.